



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 413]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 26, 2010/श्रावण 4, 1932

No. 413]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 26, 2010/SHRAVANA 4, 1932

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2010

सा.का.नि. 631(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“सं. आ. 264”

महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व)
दूसरा संशोधन आदेश, 2010

राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस राज्य के राज्यपाल द्वारा विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना के लिए महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल द्वारा पारित संकल्पों को प्रभावी बनाने के लिए महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) आदेश, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) किया ;

और उक्त आदेश 1 मई, 1994 से प्रवृत्त हुआ और उक्त आदेश के खंड (1) के उपखंड (3) के निबंधनानुसार यह 30 अप्रैल, 1999 को या ऐसी तारीख तक जो राष्ट्रपति इस निमित्त किए गए आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें, इसका अवसान होगा ;

और उक्त आदेश के अनुसरण में, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्डों का उक्त आदेश के प्रवृत्त रहने अर्थात् 30 अप्रैल, 1999 तक गठन किया है ;

और राष्ट्रपति ने उक्त आदेश के खंड 1 के उपखंड (3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संविधान आदेश 175 में महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) संशोधन आदेश, 1999 विनिर्दिष्ट किया था कि उक्त आदेश 30 अप्रैल, 2004 तक प्रवृत्त रहेगा ;

और महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) संशोधन आदेश, 1999 के अनुसरण में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्डों की अवधि का विस्तार 30 अप्रैल, 2004 तक किया था ;

और राष्ट्रपति ने उक्त आदेश के खंड 1 के उपखंड (3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संविधान आदेश 203 में महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) संशोधन आदेश, 2004 विनिर्दिष्ट किया था कि उक्त आदेश 30 अप्रैल, 2005 तक प्रवृत्त रहेगा ;

और महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) संशोधन आदेश, 2004 के अनुसरण में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्डों की अवधि का विस्तार 30 अप्रैल, 2005 तक किया था ;

और राष्ट्रपति ने उक्त आदेश के खंड 1 के उपखंड (3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संविधान आदेश 208 में महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) संशोधन आदेश, 2005 विनिर्दिष्ट किया था कि उक्त आदेश 30 अप्रैल, 2006 तक प्रवृत्त रहेगा ;

और महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) संशोधन आदेश, 2005 के अनुसरण में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्डों की अवधि का विस्तार 30 अप्रैल, 2006 तक किया था ;

और राष्ट्रपति ने उक्त आदेश के खंड 1 के उपखंड (3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संविधान आदेश 210 में महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) संशोधन आदेश, 2005 विनिर्दिष्ट किया था कि उक्त आदेश 30 अप्रैल, 2010 तक प्रवृत्त रहेगा ;

और महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) दूसरा संशोधन आदेश, 2005 के अनुसरण में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्डों की अवधि का विस्तार 30 अप्रैल, 2010 तक किया था ;

और राष्ट्रपति ने उक्त आदेश के खंड 1 के उपखंड (3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संविधान आदेश 261 में महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) संशोधन आदेश, 2010 विनिर्दिष्ट किया था कि उक्त आदेश 31 अक्टूबर, 2010 तक प्रवृत्त रहेगा ;

और महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) संशोधन आदेश, 2010 के अनुसरण में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्डों की अवधि का विस्तार 31 अक्टूबर, 2010 तक किया था ;

और महाराष्ट्र के राज्यपाल उक्त विकास बोर्डों को उक्त क्षेत्रों के हित में बना रहना समीचीन समझते हैं और राज्य सरकार के अनुमोदन पर राष्ट्रपति से उक्त आदेश की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया है ;

अतः, अब, राष्ट्रपति, उक्त आदेश के खंड 1 के उप-खंड (3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिर्दिष्ट करती हैं कि उक्त आदेश 30 अप्रैल, 2015 तक प्रवृत्त रहेगा ।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल

राष्ट्रपति

[फा. सं. 19(13)/2010-वि. 1]

वी. के. भसीन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2010.

G.S.R. 631(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 264”

The State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and The Rest of Maharashtra) Second Amendment Order, 2010

WHEREAS the President has, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution, made the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Order, 1994 (hereinafter referred to as the said Order), giving effect to the resolutions passed by the Maharashtra State Legislature for establishment of separate Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra by the Governor of that State;

AND WHEREAS the said Order came into force with effect from the 1st day of May, 1994 and in terms of sub-clause (3) of clause 1 of the said Order it shall expire on the 30th day of April, 1999 or up to such date as the President may, by order made in this behalf, specify;

AND WHEREAS, in pursuance of the said Order, the Governor of Maharashtra has set up the Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra till the said Order remains in force, that is, up to the 30th day of April, 1999;

AND WHEREAS the President, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution, read with sub-clause (3) of clause 1 of the said Order had specified in the Constitution Order 175, the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 1999 that the said Order shall remain in force up to the 30th day of April, 2004;

AND WHEREAS in pursuance of the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 1999, the Governor of Maharashtra had extended the term of the Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra up to the 30th day of April, 2004;

AND WHEREAS the President, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution, read with sub-clause (3) of clause 1 of the said Order had specified in the Constitution Order 203, the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 2004 that the said Order shall remain in force up to the 30th day of April, 2005;

AND WHEREAS in pursuance of the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 2004, the Governor of Maharashtra had extended the term of the Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra up to the 30th day of April, 2005;

AND WHEREAS the President, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution, read with sub-clause (3) of clause 1 of the said Order had specified in the Constitution Order 208, the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 2005 that the said Order shall remain in force up to the 30th day of April, 2006;

AND WHEREAS in pursuance of the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 2005, the Government of Maharashtra had extended the term of the Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra up to the 30th day of April, 2006;

AND WHEREAS the President, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution, read with sub-clause (3) of clause 1 of the said Order had specified in the Constitution Order 210, the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Second Amendment Order, 2005 that the said Order shall remain in force up to the 30th day of April, 2010;

AND WHEREAS in pursuance of the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Second Amendment Order, 2005, the Governor of Maharashtra had extended the term of the Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra up to the 30th day of April, 2010;

AND WHEREAS the President, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution, read with sub-clause (3) of clause 1 of the said Order had specified in the Constitution Order 261, the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 2010 that the said Order shall remain in force up to the 31st day of October, 2010;

AND WHEREAS in pursuance of the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 2010, the Governor of Maharashtra had extended the term of the Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra up to the 31st day of October, 2010;

AND WHEREAS the Governor of Maharashtra considers it expedient in the interest of the said areas to continue the said Development Boards and on approval of the State Government has requested the President to extend the duration of the said Order;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution, read with sub-clause (3) of clause 1 of the said Order, the President hereby specifies that the said Order shall remain in force up to the 30th day of April, 2015.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL,
President.

[F. No. 19(13)/2010-Leg. I]

V. K. BHASIN, Secy.